

अधिसूचना

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदावधि के लिए सामान्य अनुदेश, 2016 के अनुदेश-4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड से विचार-विमर्श कर निम्न वर्णित विधि अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर अग्रेत्तर आदेश तक आबद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	अधिवक्ता का नाम	पदनाम
1	श्री मोहन चन्द्र पाण्डे, वरिष्ठ अधिवक्ता	अपर महाधिवक्ता
2	श्री जगदीश प्रसाद जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता	अपर महाधिवक्ता
3	श्री बालादत्त उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता	अपर महाधिवक्ता
4	श्री बिन्देश कुमार गुप्ता	उप महाधिवक्ता
5	श्री मोहन चन्द्र तिवारी	उप महाधिवक्ता
6	श्रीमती ममता बिष्ट	उप महाधिवक्ता
7	श्री हर्षमणि रतूड़ी	उप महाधिवक्ता
8	श्री सन्दीप टण्डन	उप महाधिवक्ता
9	श्री सुभाष त्यागी	उप महाधिवक्ता
10	श्री कौस्तुबानन्द जोशी	उप महाधिवक्ता
11	श्री अमित भट्ट	उप महाधिवक्ता
12	श्री विनोद कुमार जैमिनी	उप महाधिवक्ता
13	श्री पंकज पुरोहित	उप महाधिवक्ता
14	श्री सुधीर कुमार चौधरी	उप महाधिवक्ता
15	श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान	उप महाधिवक्ता
16	श्री सुनील खेड़ा	उप महाधिवक्ता
17	श्री तेज सिंह बिष्ट	उप महाधिवक्ता
18	श्री नाथी सिंह पुण्डीर	उप महाधिवक्ता
19	श्री विनोद कुमार नौटियाल	उप महाधिवक्ता
20	श्री अनिल कुमार जोशी	अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता
21	श्री योगेश कुमार पाण्डे	अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता
22	श्री चन्द्र शेखर रावत	अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता
23	श्री गजेन्द्र सिंह सन्धू	शासकीय अधिवक्ता
24	श्री प्रेम सिंह बोहरा	सहायक शासकीय अधिवक्ता
25	श्री शेर सिंह अधिकारी	सहायक शासकीय अधिवक्ता
26	श्री टेकचन्द्र अग्रवाल	सहायक शासकीय अधिवक्ता
27	श्री जगजीत सिंह विर्क	सहायक शासकीय अधिवक्ता
28	श्री प्रतिरूप पाण्डे	सहायक शासकीय अधिवक्ता

2- उक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह एक व्यवसायिक आबन्धन है, किसी 'सिविल पद' पर नियुक्ति नहीं है। इस आबन्धन को राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताये समाप्त किया जा सकता है तथा आबद्ध अधिवक्ता भी इसे कभी भी लिखित सूचना देकर समाप्त कर सकते हैं। आबद्ध अधिवक्तागण द्वारा अपनी आबद्धता के दौरान उत्तराखण्ड राज्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के मामलों में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की आबद्धता स्वीकार नहीं करेंगे और न ही राज्य के विरुद्ध कोई विधिक परामर्श देंगे तथा वे विधि परामर्शी निदेशिका के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेंगे।

3- उक्त आबद्ध अधिवक्तागण को संलग्न शासनादेश सं0-136/XXXVI(1)/2016-43 एक(1)/2003 दिनांक 10.03.2016 के अनुसार फीस देय होगी।

4- आबद्ध अधिवक्तागण इस आशय का प्रमाण पत्र भी महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेंगे कि उक्त शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव

संख्या- (1)/XXXVI(1)/2017-105/2012 T.C. तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव

संख्या- 187 (2)/XXXVI(1)/2017-105/2012 T.C. तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
9. सम्बन्धित अधिवक्तागण।
10. ईरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(रीतेश कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव